प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
08.05.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जनसम्पर्क को सुगम बनाने के लिए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का किया शुभारम्भ।
- प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज–पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी।
- राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर ओपीएस व एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर भेदभाव करने का लगाया आरोप।
- प्रदेश के सभी ज़िला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन–लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा।
- लाहौल स्पीति ज़िला में बर्फबारी से बंद दारचा–शिंकुला सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल।

डिजिटल पास

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जनसम्पर्क को सुगम बनाने के उद्देश्य से आज राज्य सचिवालय शिमला में डिजिटल गेट पास प्रणाली और यूनिफाईड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्लेटफार्म मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल जनता व सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसम्पर्क अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली विभिन्न सरकारी विभागों को एक केंद्रीयकृत डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से बैठक संबंधी आग्रह भेजने की सुविधा भी प्रदान करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक में नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन व हिमाचल सदन और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन के कार्य की समीक्षा करते हुए परियोजना को 15 जून से पहले पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

चुनाव

प्रदेश में आगामी 17 मई को होने वाले चार नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मिया तेज हो गई है। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रमुख नेता अपने–अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं।

इस बीच प्रदेश की 3 हजार 7 सौ 54 पंचायतों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन आज बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने–अपने नामांकन पत्र भरे। किन्नौर जिला में आज विभिन्न पदों के लिए कुल 6 सौ 13 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जबकि लाहौल स्पीति में 67 नामांकन भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापिस ले सकेंगे।

सरकार–पश्चिम एशिया ब्रीफिंग

केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पांच किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि देशभर में वाणिज्यिक आपूर्ति लगभग 70 प्रतिशत तक बहाल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं है।

सिकंदर कुमार

राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ओपीएस को कर्मचारियों के हित में बताकर लागू किया, लेकिन आज पुरानी पैंशन स्कीम अपनाने वाले कर्मचारी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है, जबकि ओपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार की दरों के अनुसार केवल 45 प्रतिशत डीए मिल रहा है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि समान पद, समान कार्य और समान जिम्मेदारियों के बावजूद कर्मचारियों के बीच इस तरह का अंतर पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ओपीएस और एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर बनाए गए इस भेदभाव को तुरंत समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों को समान दर पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा हमेशा कर्मचारियों के हितों के साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी कर्मचारियों की आवाज को मजबूती के साथ उठाती रहेगी।

राज्यपाल

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के प्राचीन मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं हैं बल्कि भारत की समृद्ध सभ्यता, सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक परंपराओं के महत्त्वपूर्ण प्रतीक भी हैं। उन्होंने आज कांगड़ा जिले के प्राचीन बैजनाथ मंदिर में दर्शन किए और देश व प्रदेश के लोगों की सुख–समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने हिमाचल की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

लोक अदालत

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल 9 मई को प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63 हजार मामले प्राप्त हुए हैं।

सड़क बहाल

सीमा सड़क संगठन बी.आर.ओ. ने दारचा–शिंकुला सड़क पर बर्फ हटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लाहौल स्पीति ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपायुक्त किरण भढ़ाणा ने इस सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति ज़िला संवाददाता

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आज शिमला में शुरू हुआ। कोटशेरा कॉलेज शिमला और देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफैसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मलेन को आज के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

सम्मेलन में विशेषज्ञ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, पर्यावरण व तकनीकी सहित सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्ययोजना तैयार करेंगे ताकि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया सके।

राकेश जम्वाल

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और दैनिक खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है, जो इस सरकार की विफल आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास न तो आर्थिक दृष्टि है और न ही वित्तीय प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय केवल महंगाई बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की आवाज उठाती रहेगी।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जनसम्पर्क को सुगम बनाने के लिए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का किया शुभारम्भ।
- प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज–पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी।
- राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर ओपीएस व एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर भेदभाव करने का लगाया आरोप।
- प्रदेश के सभी ज़िला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन–लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा।

- लाहौल स्पीति ज़िला में बर्फबारी से बंद दारचा–शिंकुला सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल।

———————————————